आई. एस. तिवाना और अमरजीत चौधरी, के समक्ष जे.जे.

गुलशन कुमार और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक एवं

अन्य,-प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 5631

6 अक्टूबर 1989.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश-विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने और विशेषज्ञता में परिवर्तन के लिए लगाई गई शर्तें-ऐसी शर्तें-चाहे सार्वजनिक हित में हों।

माना गया कि जिन याचिकाकर्ताओं की उत्कट इच्छा विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की है, उन्हें गुलशन कुमार और अन्य बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य (अमरजीत चौधरी, जे.) के उचित रूप से तैयार किए गए नियमों और विनियमों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्हें मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में पेश किया गया है। .

हमारे देश में मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी है। चाहे वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो या डिप्लोमा पाठ्यक्रम, राज्य को शिक्षण संकाय, उपकरणों और अन्य मदों जैसे वजीफा और फेलोशिप आदि पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे अत्यधिक मांग वाले और महंगे पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बहुत सीमित हैं। जनहित का आह्वान है कि जिन लोगों को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है, उन्हें इसे पूरा करना चाहिए और बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और यदि वे भारत के संविधान में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें उचित रूप से संशोधित करने या हटाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस की शर्तों में हमें कोई भी पेंच ढीला नहीं दिखता है, जो एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए चयनित होने के बाद, किसी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम से कम नहीं, न्यायिक लेंस को ठीक करने और किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए कहता हो। . सीमित सीटों को ध्यान में रखते हुए, केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर, उक्त पाठ्यक्रम को बीच सत्र में छोड़ने और सीट के रूप में उस पर खर्च किए गए पैसे और कीमती समय की परवाह किए बिना अन्य विषयों में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि बीच सत्र में खाली करने की अनुमति दी जाती है तो उसे किसी अन्य छात्र को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो। .

(पैरा 6).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि 'मामले के रिकॉर्ड मंगाने और उसका अवलोकन करने के बाद: -

(i) वर्ष 1989 के प्रॉस्पेक्टस और सूचना बुलेटिन के अध्याय IV के सर्टिओरीरी क्वैशिंग कंडीशन नंबर 4 (ii) से 4 (iv) की प्रकृति में एक रिट जारी करना, जो अनुबंध पी/एल के रूप में संलग्न है;

(ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे;

(iii) उन्होंने उत्तरदाताओं को प्रस्ताव की सूचना देने से मना कर दिया क्योंकि मामला अत्यावश्यक था;

(iv) जिन अनुलग्नकों को छूट दी गई है उनकी प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना;

(v) उन्होंने याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की लागत की अनुमति दी।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता नंबर 1 को एम.एस. ऑर्थोपेडिक्स और एम.डी. रेडियोलॉजी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता नंबर 2 को एम.डी. पेडियाट्रिक्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

गुलशन कुमार, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रांत शर्मा, अधिवक्ता।

8. एस. मलिक, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए।

निर्णय

अमरजीत चौधरी, जे.

(1) याचिकाकर्ता गुलशन कुमार और राकेश सेठ ने क्रमशः 1983 और 1985 में मेडिकल कॉलेज, रोहतक से एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने नवंबर 1985 में ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा कोर्स प्राप्त किया और उसके बाद वह फार्माकोलॉजी विभाग में एमडी डिग्री कोर्स में शामिल हो गया, जिसकी अवधि 3 मई, 1989 को समाप्त होनी थी।

याचिकाकर्ता संख्या 2 ने मई 1987 में बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा में प्रवेश लिया, लेकिन उसे उत्तीर्ण करने में असफल रहा। उन्होंने जुलाई, 1988 में रेडियोलॉजी में प्रवेश लिया और इस बीच वे सिविल कोर्ट के आदेशों के तहत बाल स्वास्थ्य में डिप्लोमा में पूरक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसके लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने इस दलील पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने बाद में रेडियोलॉजी में डिप्लोमा में प्रवेश लिया था। . रेडियोलॉजी पाठ्यक्रम की अवधि जून, 1989 में समाप्त होने वाली थी। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने एम.एस. ऑर्थोपेडिक्स और एम.डी. रेडियोलॉजी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। इसी तरह याचिकाकर्ता नंबर 2 ने भी एम.डी. पीडियाट्रिक्स, एक डिग्री कोर्स और एम.डी रेडियोलॉजी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने पूरी तरह से पात्र होने के कारण संबंधित विषयों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इस दलील पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, रोहतक द्वारा जारी

प्रॉस्पेक्टस और सूचना के बुलेटिन में निर्धारित शर्तों के अनुसार - प्रतिवादी नंबर 2 वे आवेदन करने के लिए अयोग्य थे।

(2) याचिकाकर्ताओं ने, इसलिए, इस रिट याचिका के माध्यम से उपरोक्त प्रॉस्पेक्टस की शर्त संख्या 4 (ii), (iii) और (iv) को रद्द करने की एक रिट जारी करने की प्रार्थना की, जो उनके अनुसार प्रवेश के लिए आवेदन करने की राह में बाधक थी। .

(3) रिटर्न में प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता सत्र 1989-90 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं थे, क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 पहले से ही एक डिग्री हासिल कर रहा था। यानी एम.डी. फार्माकोलॉजी, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 हालांकि रेडियोलॉजी में डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र था क्योंकि वह उसी विषय में डिप्लोमा कोर्स कर रहा था, लेकिन वह एम.डी. पेडियाट्रिक्स में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं था।

(4) इस याचिका में प्रॉस्पेक्टस की शर्त संख्या 4(ii) से (iv) के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये शर्तें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ प्रॉस्पेक्टस में डाली गई हैं। . यदि याचिकाकर्ताओं को पता होता कि वे भविष्य में प्रवेश के लिए अयोग्य होंगे तो उन्होंने पहले प्रवेश नहीं मांगा होता। प्रतिवादी विश्वविद्यालय का दायित्व था कि जिस समय उन्होंने प्रवेश लिया था उसी समय उन्हें प्रवेश की शर्तों के बारे में सूचित किया था।

(5) रद्द किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस की प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैं: -

"4(ii) एक छात्र जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, वह किसी अन्य विषय में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसे पिछली डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को वजीफा का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) एक छात्र जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, वह किसी अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) एक छात्र जो किसी विषय में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, वह किसी अन्य विषय में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम या उसी विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) माना जाता है कि जब याचिकाकर्ता नंबर 1 ने एमएस ऑर्थोपेडिक्स के लिए आवेदन किया था तब उसने अपना पिछला कोर्स यानी एम.डी. फार्माकोलॉजी पूरा नहीं किया था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 अभी भी रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कर रहा था जब उसने एम.डी. पेडियाट्रिक्स और एम.डी रेडियोलॉजी में प्रवेश मांगा था। तो स्पष्ट रूप से उपरोक्त शर्तों में निहित प्रावधानों के अनुसार, वे उनके द्वारा आवेदन किए गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं थे। लेकिन याचिकाकर्ताओं की शिकायत जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि प्रॉस्पेक्टस की उपरोक्त शर्तों के प्रावधान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि इन शर्तों को लागू करके उत्तरदाताओं ने अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त

करने की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया है। . लेकिन याचिकाकर्ता यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी प्रावधान के खिलाफ कैसे हैं। इसके अलावा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियम अनिवार्य नहीं हैं। यहां तक कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय भी अपने स्वयं के नियम और विनियम बना सकता है। जिन याचिकाकर्ताओं की उत्कट इच्छा विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की है, उन्हें उचित ढांचे को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारी सुविचारित राय में नियम और विनियम मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए हैं। हमारे देश में मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी है। चाहे वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो या डिप्लोमा पाठ्यक्रम, राज्य को शिक्षण संकाय, उपकरणों और अन्य मदों जैसे वजीफा और फेलोशिप आदि पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे अत्यधिक मांग वाले और महंगे पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बहुत सीमित हैं। जनहित की मांग है कि जिन लोगों को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है, उन्हें इसे पूरा करना चाहिए और बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और यदि वे भारत के संविधान में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें उचित रूप से संशोधित करने या हटाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस की शर्तों में, हमें कोई भी पेंच ढीला नहीं दिखता है जो एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए चयनित होने के बाद एक अभ्यर्थी के लिए न्यायिक लेंस को ठीक करने और किसी भी विसंगति को दूर करने की मांग करता है। एक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, सीमित सीटों को ध्यान में रखते हुए, योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर, उक्त पाठ्यक्रम को बीच सत्र में छोड़ने और सीट के रूप में खर्च किए गए धन और कीमती समय की पूरी तरह से उपेक्षा करके अन्य अनुशासन में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि मध्य सत्र में खाली करने की अनुमति किसी अन्य छात्र को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो।

(7) याचिकाकर्ताओं ने अपने विवादों का समर्थन करते हुए परवीन कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1] और पंजाब राज्य बनाम डॉ. हरनेक सिंह [2] में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। हमें डर है, ये अधिकारी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

परवीन कुमार के मामले में (सुप्रा) याचिकाकर्ता ने एम.बी.बी.एस परीक्षा उत्तीर्ण करने और पहले चिकित्सा की विशेषज्ञता में और उसके बाद बाल चिकित्सा की विशेषज्ञता में घरेलू नौकरी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद सिल्ड हेल्थ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आवश्यकताओं में से एक था। .

[1] 1988 का सीडब्ल्यूपी 2335।

[2] एल. 1989 का पीए 185|

वास्तव में, उन्होंने बाल स्वास्थ्य में अपना डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था, लेकिन मौजूदा मामले में जब याचिकाकर्ताओं ने अन्य विषयों में प्रवेश मांगा तो उन्होंने अपना संबंधित पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था। इसी तरह, डॉ. हरनेक सिंह का मामला (सुप्रा) भी अलग है, क्योंकि वह किसी विशेष या डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का मामला नहीं था। उस मामले में याचिकाकर्ता ने एनेस्थीसिया में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद अमृतसर और पटियाला में राज्य मेडिकल कॉलेजों में रजिस्ट्रार/डेमॉन्स्ट्रेटर के पद के लिए आवेदन किया था। वहां याचिकाकर्ता के चयन पर भी वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर विचार किया जाना था। लेकिन हाथ में मामला अलग-अलग लाइनों पर है। इस प्रकार, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस की शर्तें 4 (ii) से (iv) काफी क्रम में हैं, पूरी तरह से वैध और सार्वजनिक हित में हैं। प्राकृतिक न्याय के नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं है.

(8) परिणामस्वरूप, यह याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh